भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-321

उत्तर दिनांक - 28/11/2024 को दिया गया

सभी के लिए वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा

321. डा. सिकंदर कुमार

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 2047 तक लगभग 100 गीगावाट परमाणु क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने की अभिकल्पना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन में सहायता करने हेतु परमाणु ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों के लिए भंडारण सहित पर्याप्त अवसंरचना निर्माण के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(घ) क्या देश भर में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए नए आविष्कार किए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) व (ख) वर्तमान में, 8180 मेगावाट की वर्तमान नाभिकीय विद्युत क्षमता को वर्ष 2031-32 तक 22480 मेगावाट तक बढ़ाने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। जबकि वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य में भारत के ऊर्जा परिवर्तन संबंधी विभिन्न अध्ययनों से वर्ष 2047 तक राष्ट्रीय नाभिकीय क्षमता को 100 गीगावाट तक किए जाने की आवश्यकता का अनुमान है, उन अध्ययनों की सिफारिश को भविष्य में अपनाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है।

(ग) नाभिकीय ऊर्जा, ऊर्जा का एक आधार भार स्रोत है और ग्रिड में एकीकरण के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं है जैसे कि ऊर्जा के अस्थायी स्रोतों (पवन, सौर आदि जैसी नवीकरणीय ऊर्जा) के लिए आवश्यक है।

(घ) हां। अभिकल्प में नवाचार, बेहतर प्रचालन और अभिरक्षण पद्धतियों को अपनाने, उन्नयन के क्रियान्वयन आदि द्वारा मौजूदा नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की संरक्षा और प्रचालन निष्पादन को बढ़ाने का प्रयास भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में एक सतत प्रक्रिया है।

*****